POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2021/अंक 02

मासिक प्रेषण दि. 8 फरवरी, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

# ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

प्रकाशन की तिथि : 01 फरवरी, 2021 मूल्य 50 पैसे

## आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! देश में मास्क और दो गज की दूरी के साथ कोरोना टीकाकरण की भी शुरुआत हो चुकी है। वैक्सीन तैयार करने वाले वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों पर गर्व है। कोरोना के चलते देश की स्वास्थ्य संरचना बुनियादी रूप से मजबूत हुई है। जहां आयुष मंत्रालय को विज्ञानसम्मत बनाने के प्रयास हुए हैं, वहीं चिकित्सा जगत को नवीनतम प्रौद्योगिकी ने भी नई ऊंचाई दी है।

खास बात यह है कि सरकार का शोध और विकास पर ध्यान केंद्रित हुआ है। कोरोना टीके के शोध के साथ-साथ वैज्ञानिकों ने कई अन्य संक्रामक बीमारियों के रोकथाम के टीकों पर भी 50 फीसदी तक सफलता प्राप्त की है। जाहिर है हम 2021 में स्वास्थ्य से संबंधित कई चुनौतियों से निपटने में ज्यादा सक्षम होंगे।

यह भी सच है, कोरोना ने हमारे रोजगार, कारोबार और दूसरे कई मामलों के हर पहलू को अस्त-व्यस्त किया है। लेकिन देश के नागरिक मुकाबले के लिए मिल-जुल कर उठ खड़े हुए। इस तथ्य को हमारे नीति आयोग ने भी स्वीकार किया है। नीति आयोग आशान्वित है कि इस वर्ष विकास की अच्छी रफ्तार रहेगी और रोजगार एवं कारोबार को नए पंख लगेंगे। कोरोना काल में सिर्फ कृषि ही ऐसा क्षेत्र था जिसकी वृद्धि दर सकारात्मक रही।

इसके लिए कृषि क्षेत्र को और मजबूत बनाने और जरूरी सुधार के कदम उठाए गए हैं। इससे कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और भारत प्रमुख कृषि निर्यातक देश के रूप में उभरेगा। रसायनमुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी बड़े स्तर पर काम हो रहा है। इससे लागत घटेगी और जैविक बाजार में हमारी खास पहचान भी बनेगी। इससे किसानों का काफी फायदा बढ़ेगा।

## एफएसएसएआई ने खाद्य पदार्थों में घटाई ट्रांस फैट की मात्रा

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनियाभर में हर साल करीब 5.4 लाख मौतें वसायुक्त अम्ल (ट्रांस फैटी एसिड) के सेवन से होती हैं। यह सेहत के लिए हानिकारक होता है। इसके ज्यादा सेवन से हार्ट अटैक और कोरोनरी आर्टरी बीमारियों से मौत का ज्यादा खतरा रहता है। इसके अलावा यह खराब याददाश्त और डिमेंशिया के खतरे से भी जुड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खतरे को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2023 तक खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट्स के उन्मूलन की मांग की है।

इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की मात्रा को घटाया है। उसने एक संशोधन के जरिए ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा 5 फीसदी से घटाकर 3 फीसदी कर दिया है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एक जनवरी 2021 से तेल और फैट में ट्रांस फैटी एसिड की अधिकतम सीमा वजन में 3 फीसदी से ज्यादा नहीं होगी। वर्ष 2022 तक इस सीमा को घटाकर 2 फीसदी किए जाने पर भी मंथन जारी है।

संशोधित विनियमन खाने वाले रिफाइन तेल, वनस्पति, मार्जरीन और अन्य कुकिंग के माध्यमों एवं औद्योगिक प्रक्रिया के तहत तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों पर लागू होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ट्रांस फैट या ट्रांस फैटी एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो या तो प्राकृतिक या औद्योगिक स्त्रोत से मिलते हैं। यह नया विनियमन तत्काल रूप से प्रभावी हो गया है।

## लापरवाही से विवाहिता की मौत, अस्पताल पर 15 लाख का हर्जाना

राज्य उपभोक्ता आयोग की सर्किट बैंच बीकानेर में मुकेश कुमार नाहटा ने बीकानेर के प्रताप प्रसूति गृह, टोडा हाउस के खिलाफ अपील दर्ज कराई। मामले के अनुसार परिवादी मुकेश कुमार व उसकी पत्नी अनुपमा ने चार साल तक संतान नहीं होने पर प्रताप प्रसूती गृह में संपर्क किया। अस्पताल प्रबंधन ने 14 जुलाई 2007 को अनुपमा की लेप्रोस्कोपी की, लेकिन इससे पहले होने वाली जांचे नहीं की।

इस दौरान सही जगह जांच निडल नहीं डालने के चलते अनुपमा को इंजरी हो गई और खून बहने लगा। इसके बाद ऑपरेशन भी कर दिया गया। जांच निडल की स्प्रिंग को लापरवाही से पीछे खेंचने से उसका नुकिला सिरा आंत तक चला गया और नसें कट गई। इससे अनुपमा की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मामला उपभोक्ता मंच में दर्ज कराया था, लेकिन फैसले से संतुष्ट नहीं होने पर यह अपील दर्ज की है।

मामले की सुनवाई पर आयोग ने चिकित्सकीय लापरवाही मानते हुए बीकानेर के प्रताप प्रसूति गृह पर 15 लाख 21 हजार 500 रुपए का हर्जाना लगाया। साथ ही हर्जाना राशि पर 15 जुलाई 2009 से 9 फीसदी ब्याज भी देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने आदेश में कहा कि अस्पताल में इलाज के लिए पर्याप्त संसाधन तक नहीं थे, इस कारण अनुपमा की मौत हुई है।

## 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार, 2020

'कट्स' द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय ग्रामीण भित्ती-पत्र 'ग्राम गदर' अपने प्रकाशन के 39 वर्ष पूरे कर रहा है। अतः हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण संचार के क्षेत्र में लेखन और उत्कृष्ठ पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु पत्रकार बन्धुओं से प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समसामयिक मुद्दों पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2020 का विषय जिस पर उत्कृष्ठ पत्रकारिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जा रही हैं, वह है:

### 'कोरोना महामारी के दौरान बढ़ती बेरोजगारी'

ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार के अन्तर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा चुने गये पत्रकार को 10,000 (दस हजार) रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कृपया प्रविष्टियां भेजते समय निम्न उल्लेख/संलग्न अवश्य करें-

- अपना पूरा नाम व पता पिनकोड सहित। • टेलीफोन/मोबाइल नम्बर।
- पत्रकारिता के लिए जिस समाचार पत्र से जुड़े हैं/थे या स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं तथा कब से (पूर्ण विवरण सहित)।
- वर्ष 2020 के दौरान आपके नाम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख व खबरों की प्रेस कटिंग व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संलग्नीकरण।

प्रविष्टियां हमें 31 मार्च, 2021 तक नीचे लिखे पते पर अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

**कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)**, डी -217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302 016 (राजस्थान) फोन: 0141-2282821, फैक्स: 0141-2282485, 4015395

ई-मेल: cart@cuts.org, वेबसाईट: www.cuts-international.org

## घायलों का तत्काल उपचार अनिवार्य

सड़क दुर्घटना में घायलों को नजदीकी निजी अस्पतालों में पैसे जमा कराए बिना अब तत्काल इलाज उपलब्ध हो सकेगा। घायल का इलाज करने से मना करने के मामलों में संबंधित निजी अस्पताल एवं डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुसार घायल व्यक्ति को लोग पास के निजी अस्पताल में ले जाते हैं जहां पहले रजिस्ट्रेशन और ईलाज के लिए रुपए जमा कराने को कहा जाता है। इससे घायल व्यक्ति के जीवन का खतरा बढ़ जाता है। अब कोई निजी अस्पताल व डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकेगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। घायल को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

## नवाचारों से आएगा कृषि में बदलाव

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि आने वाले समय में किसानों को नवाचारों के माध्यम से कृषि में नए बदलाव लाने होंगे। उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग और कृषि उत्पादों में मूल्य वृद्धि (वैल्यू एडिशन) की संभावनाएं बताते हुए कहा कि इससे किफायती, टिकाऊ, गुणवत्तापूर्ण और उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन संभव हो सकेगा। इससे किसानों की आमदनी तेजी से बढ़ सकेगी।

उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका अहम है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है। भारत के नौजवान तकनीकी क्षेत्रों और इनोवेशन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो खेती और किसानी के लिए काफी लाभदायक साबित हो रहा है।

## भूजल दोहन से बढ़ेगा जल संकट

राज्य सरकार ने पेयजल, घरेलू उपयोग और कृषि उपयोग सहित पांच श्रेणियों के लिए ट्यूबवेल व नलकूप खोदने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने की अनिवार्यता हटाई तब से ही प्रदेश में नलकूप-बोरिंग धड़ल्ले से खोदे जा रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भूजल स्तर बुरी तरह गड़बड़ा जाएगा। अगर संभले नहीं तो गंभीर जल संकट गहराएगा। सबसे नीचे का पानी आपातकाल के लिए सुरक्षित माना जाता है। दोहन बढ़ने से पानी पाताल में चला जाएगा। इससे बोरिंग-नलकूपों के सूखने और उम्र घटने से गंभीर जल संकट पैदा होगा।

## अभी भी लाखों लगा रहे हैं अंगूठा

अभी भी प्रदेश में 45 साल से ज्यादा उम्र के करीब 4 लाख 20 हजार पुरुष और महिलाएं अनपढ़ हैं। इनमें पुरुषों का आंकड़ा एक लाख 15 हजार है। वहीं अनपढ़ महिलाओं की संख्या 3 लाख 5 हजार है। यह सभी अभी भी कागजों पर अंगूठा लगा रहे हैं। इनमें ज्यादातर ग्रामीण पुरुष और महिलाएं हैं।

इससे जाहिर है कि करीब 20 सालों से हर साल सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर साक्षरता के लिए कई अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन नतीजा शून्य है। अभियान कागजों में ही सिमट कर रह जाते हैं। इस बार फिर पंचायत स्तर पर समितियों का गठन कर साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है।

## गृहिणियों के काम को कम न आंके

'यह रूढ़िवादी सोच है कि जो महिलाएं घर में रहती हैं, वे काम नहीं करती। इसे बदलना चाहिए। महिलाएं घरों में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा काम करती हैं। उनके काम का कोई आर्थिक मोल नहीं माना जाता। यह धारणा खत्म होनी चाहिए। गृहिणी बिना वेतन घर का काम करती है, जिसका परिवार के आर्थिक विकास में बड़ा योगदान होता है।'

उक्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में मुआवजा राशि बढ़ाते हुए, बीमा कंपनी को 9 फीसदी ब्याज सहित 33 लाख 20 हजार रुपए उसके परिजनों को अदा करने के आदेश दिए।

## सरकार देगी कृषि मंत्रालय को नया रूप

कृषि क्षेत्र में तीन बड़े कानून के जरिए बड़े बदलाव की पहल कर चुकी मोदी सरकार अब कृषि मंत्रालय के स्वरूप में भी बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। अपने दूसरे कार्यकाल में जल से जुड़े सभी मंत्रालयों को एक साथ जोड़कर जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया था। इसके तहत बड़े बजट के साथ हर घर नल की महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई।

इसी तर्ज पर खेती और दूसरी ऐसी गतिविधियों से जुड़े मंत्रालयों को एक साथ जोड़कर कृषि मंत्रालय को भी एक बड़ा स्वरूप दिया जा सकता है। यह मंत्रालय काफी बड़ा होगा और इसके लिए बजट प्रावधान भी काफी बढ़ जाएगा। इससे किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य जल्दी पूरा होगा। कृषि विशेषज्ञ इस कदम को किसानों के लिए हितकारी बता रहे हैं।

## कर्मचारी खा गए गरीबों का गेहूं

प्रदेश के 20 हजार से ज्यादा सरकारी कर्मियों के परिवारों द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) में दो रुपए किलो कीमत पर गेंहू उठाने के मामलों में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देश पर जिला कलेक्टरों ने 5000 से ज्यादा कर्मचारियों को वसूली के नोटिस थमाए हैं। अभी नोटिस देने का यह सिलसिला जारी है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अब इन कर्मचारियों से 27 रुपए किलो के हिसाब से वसूली करेगा। गौरतलब है कि यह योजना 2013 में शुरू हुई थी। प्रदेश में सात वर्षों से नियमों के विपरीत सरकारी कर्मी गरीबों का गेहूं खा रहे थे।

## प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी

'पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक की रोकथाम तथा ई-वेस्ट के कलेक्शन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

'कट्स' द्वारा आयोजित 'ग्रीन एक्शन वीक' अभियान के तहत राज्य स्तरीय परिचर्चा में नगर निगम जयपुर ग्रेटर के वार्ड नंबर 51 की पार्षद सुखप्रीत बंसल ने मुख्य अतिथि के रूप में उक्त विचार रखे।

कार्यक्रम के प्रारंभ में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने बताया कि सतत् उपभोग को बढ़ावा देने के लिए स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कंजरवेशन के सहयोग से विश्व स्तर पर 'ग्रीन एक्शन वीक' अभियान संचालित है।

## कोरोना महामारी के दौरान जैविक उत्पादों की बिक्री और खपत में हुई वृद्धि

करीब 91 प्रतिशत जैविक उत्पाद विक्रेताओं और 89 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि दस महीनों में कोरोना महामारी के दौरान जैविक उत्पाद की बिक्री और खपत में पर्याप्त वृद्धि हुई है। हाल ही 'कट्स' इंटरनेशनल द्वारा राजस्थान के दस प्रमुख जिलों में जैविक उत्पादों की बिक्री एवं उपभोग पर कराए गए एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण सर्वेक्षण में ऐसे कई निष्कर्ष सामने आए हैं। यह बढ़ते रुझान नई जीवनशैली की शुरुआत के संकेत हैं। करीब 90 फीसदी उपभोक्ताओं ने माना है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए जैविक उत्पादों का उपभोग लाभदायक है।

सर्वेक्षण में करीब 72 फीसदी उपभोक्ताओं का मानना रहा है कि जैविक उत्पाद गैर-जैविक उत्पादों की अपेक्षा ज्यादा मंहगे हैं। तथापि, एक अन्य प्रश्न के जवाब में 86 फीसदी उपभोक्ताओं ने कहा कि भविष्य में जैविक उत्पादों की खपत और उपभोग दोनों ही बढ़ेंगे। वहीं करीब 91 प्रतिशत विक्रेताओं का कहना है कि कोरोना काल के 10 महीनों में जैविक उत्पादों की बिक्री और मांग में वृद्धि हुई है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में 62 फीसदी में से 55 फीसदी विक्रेताओं ने बताया कि वे जैविक उत्पाद सीधे किसानों से खरीदते हैं। करीब 46 प्रतिशत विक्रेताओं का मानना है कि उपभोक्ता जैविक उत्पादों की खरीद के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी उपयोग करते हैं। सर्वेक्षण से खासतौर पर यह उभरकर सामने आया कि अब लोग खानपान के मामले में एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे जैविक उत्पादों के उपभोग और बिक्री दोनों में बढ़ोतरी होगी।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485